कपास में घटाया, बाकी में मंडी शुल्क बढ़ाया

500 करोड़ रुपए से अधिक अतिरिक्त मिलेंगे

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 9 जून. राज्य सरकार ने प्रदेश के कपास किसानों को राहत देते हुए कपास पर मंडी शुल्क को आधा फीसदी घटा दिया है, अब तक एक फीसदी मंडी शुल्क देना होता था, लेकिन अब आधा फीसदी ही देना होगा.

मंडी शुल्क को आधा फीसदी बढ़ा दिया गया है. अब तक बाकी उपज पर एक फीसदी मंडी शुल्क लगता था, लेकिन अब 1.50 फीसदी लगेगा. इससे प्रतिवर्ष 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी होगी, जो कि किसान और उनसे जुड़े कामों पर ही खर्च की जाएगी. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में संपन्न कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव को हरी झंडी दी है. कपास जिनिंग मिलों की जरुरत को देखते हुए कपास पर मंडी शुल्क को आधा फीसदी किया गया है. प्रदेश में लगभग 158 कपास जिनिंग मिलें है, जिनकी प्रसंस्करण क्षमता लगभग 13 लाख मीट्रिक टन है. प्रदेश में कपास पर मंडी फीस की दर में कमी किए जाने से जिनिंग मिलों के द्वारा अन्य पड़ोसी राज्यों में पलायन की अपेक्षा प्रदेश में ही व्यवसाय करने को प्राथमिकता दी जाएगी जिससे रोजगार में तथा जीएसटी संग्रहण में बढ़ोतरी होगी. यहां बता दें कि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में भी कपास पर महज आधा फीसदी ही मंडी शुल्क लिया जाता है. इसके अलावा एम.पी. स्टेट सिविल सप्लाई कारपोरेशन लि. को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक यानी एक वर्ष तक की अवधि के लिए 29,500 करोड़ रूपये की नि:शुल्क शासकीय प्रत्याभूति उपलब्ध कराई गई है.

इधर कैबिनेट ने बाकी उपज पर मंडी शुल्क को एक रुपये से बढ़ाकर 1.50 रुपये किए जाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है. इस तरह इसमें आधा फीसदी की बढ़ोतरी हो गई है. राज्य सरकार का तर्क है कि इस राशि से जिलों में कोल्डस्टोरेज,वेयरहाउस प्रसंस्करण इकाईयों एवं लॉजिस्टिक सुविधाओं को प्रोत्साहन मिलेगा. इस शुल्क राशि में से 50 पैसे विपणन विकास निधि के अंश के रूप में किसानों के कल्याण में उपयोग किया जायेगा. निराश्रित शुल्क को यथावत् 20 पैसे रखा जायेगा. इस वृद्धि से इस वर्ष में लगभग 500 करोड़ रूपये की अतिरिक्त आय होना संभावित है.

यह निर्णय भी लिए

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत राज्य आईटी. संवर्ग परामर्श सेवाओं के लिए अनुदान और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य योजना 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक की अवधि तक निरंतर संचालन के लिए 235 करोड़ 63 लाख रूपये की स्वीकृति.

भाजपा पर राजनीतिक षडयंत्र का आरोप

विशेष संवाददाता

भोपाल, 9 जून. पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ताक पर रखने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस की सीट छीनने के उद्देश्य से विभिन्न राजनीतिक हथकंडों का सहारा ले रही है.

राज्यसभा चुनाव को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच कमलनाथ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के विधायकों को लेकर जा रही फ्लाइट को जानबूझकर विलंबित किया गया, जिससे पार्टी को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ा. उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की चुनावी रणनीति को प्रभावित करने का प्रयास था.

वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्रों पर भाजपा द्वारा की गई आपत्ति की भी आलोचना की. उन्होंने इसे दुर्भावनापूर्ण और राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित कदम बताया.

कांग्रेस इन राजनीतिक हथकंडों से डरने वाली नहीं

कमलनाथ ने नामांकन प्रक्रिया के दौरान विधानसभा परिसर में भाजपा नेताओं द्वारा किए गए कथित हंगामे की भी निंदा की. कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस भाजपा के इन 'राजनीतिक हथकंडों' से डरने वाली नहीं है. उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में भाजपा को कई मोर्चों पर झटके लगेंगे. उन्होंने कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद कांग्रेस एकजुट, मजबूत और आत्मविश्वास से भरी हुई है तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने के हर प्रयास का डटकर मुकाबला करेगी.

एक नजर में

देवास ननि पर हाथ से मैला उठवाने के आरोप

देवास. राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त प्रताप करोसिया के देवास दौरा कार्यक्रम के दौरान प्राप्त एक शिकायत के आधार पर नगर निगम देवास के अधिकारियों के विरुद्ध जांच के निर्देश जारी किए गए हैं. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का नियोजन एवं प्रतिषेध अधिनियम, 2013 लागू होने के बावजूद नगर निगम देवास में कार्यरत सफाई कर्मचारियों तथा आउटसोर्स कर्मचारियों से बिना सुरक्षा उपकरणों के नालों, नालियों एवं चेंबर लाइनों की सफाई कराई जा रही है.

5 हजार रुपए की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार

कटनी. लोकायुक्त की टीम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए स्लीमनाबाद तहसील के ग्राम कौड़िया में पदस्थ पटवारी स्वयं प्रकाश मेहरा को 5 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि पटवारी ने सीमांकन करने के नाम पर शिव कुमार जायसवाल कौड़िया निवासी से पांच हजार रुपये की रिश्वत की मांग कर रहा था. शिकायत की पुष्टि होने पर लोकायुक्त ने जाल बिछाकर कार्रवाई की और आरोपी को रिश्वत की राशि लेते समय पकड़ लिया गया. कार्रवाई के बाद लोकायुक्त टीम द्वारा आरोपी पटवारी से पूछताछ की जा रही है.

मानसून की दस्तक के करीब है मध्यप्रदेश

05 डिग्री गिर सकता है पारा

15 से 18 के बीच आएगा मानसून

भोपाल, 9 जून. मध्य प्रदेश में दक्षिण-पश्चिम मानसून की एंट्री अब नजदीक है. मौसम विभाग के अनुसार 15 से 18 जून के बीच मानसून प्रदेश में प्रवेश कर सकता है. इससे पहले प्री-मानसून गतिविधियों के चलते कई जिलों में आंधी, बारिश और बादल छाने का दौर जारी रहेगा.

नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, जबलपुर, सिवनी, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, शहडोल और बालाघाट सहित कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने 10 और 11 जून को भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में लू चलने की चेतावनी भी जारी की है. सोमवार को मंडला प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा छिंदवाड़ा, खजुराहो, दमोह और मलाजखंड में भी तापमान 42 डिग्री के आसपास पहुंचा. भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है. वहीं इंदौर, उज्जैन, धार, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर में भी बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और कहीं-कहीं बारिश हो सकती है.

कई जिलों में बारिश का अलर्ट

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है. चक्रवाती परिसंचरण, ट्रफ लाइन, पश्चिमी विक्षोभ और सक्रिय प्री-मानसून सिस्टम के कारण मौसम का मिजाज लगातार बदलता रहेगा, जो मानसून के आगमन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बना रहा है.

बसों का किराया तय करने अगले सप्ताह होगी बैठक

भोपाल. परिवहन विभाग आगामी सप्ताह में सार्वजनिक बसों के किराया निर्धारण के लिए किराया निर्धारण समिति की बैठक आयोजित करेगा. बैठक में बस किराए से संबंधित प्रस्तावों पर विचार विमर्श होगा. आगामी बैठक को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए दो बस ऑपरेटर प्रतिनिधियों को बैठक में शामिल करेंगे. जिससे सर्वसम्मति से लोक-हितैषी निर्णय लिया जा सके. वर्ष 2010 में गठित स्थाई समिति में प्रमुख सचिव परिवहन, आर्थिक सलाहकार वित्त, आयुक्त वाणिज्यिक कर और परिवहन आयुक्त और परिवहन आयुक्त द्वारा नामांकित दो बस ऑपरेटर प्रतिनिधि शामिल हैं.

983 नव आरक्षक मध्यप्रदेश पुलिस में शामिल

विशेष संवाददाता

भोपाल, 9 जून. मध्यप्रदेश पुलिस को मंगलवार को 983 नव प्रशिक्षित आरक्षकों के रूप में बड़ी मजबूती मिली. पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय (पीटीसी), इंदौर में लगभग एक वर्ष के कठोर एवं अनुशासित प्रशिक्षण के बाद 78वें बैच के आरक्षक भव्य दीक्षांत परेड के साथ औपचारिक रूप से पुलिस बल की मुख्यधारा में शामिल हो गए. इस बैच में 787 महिला और 196 पुरुष आरक्षक शामिल हैं.

दीक्षांत परेड की सलामी पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने मुख्य अतिथि के रूप में ली और परेड का निरीक्षण किया. समारोह में पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, प्रशिक्षुओं के परिजन तथा अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे.

अपने संबोधन में महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने कहा कि पुलिस की सबसे बड़ी ताकत उसके अधिकार या हथियार नहीं, बल्कि जनता का विश्वास है. उन्होंने नव आरक्षकों से ईमानदारी, संवेदनशीलता और पेशेवर दक्षता के साथ जनता की सेवा करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि पुलिस के पास आने वाला पीड़ित व्यक्ति केवल कानूनी सहायता ही नहीं, बल्कि भरोसा, सहानुभूति और न्याय की अपेक्षा भी लेकर आता है.

महानिदेशक ने आगामी सिंहस्थ-2028 को पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बताते हुए सुरक्षा, यातायात, भीड़ नियंत्रण और आपदा प्रबंधन में नव आरक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर विश्वास जताया.

मकवाणा ने कहा कि आधुनिक अपराधों का स्वरूप तेजी से बदल रहा है और साइबर अपराध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा डिजिटल माध्यमों का दुरुपयोग नई चुनौतियां बनकर उभर रहा है. ऐसे में पुलिसकर्मियों का तकनीकी रूप से दक्ष, मानसिक रूप से संतुलित और नैतिक रूप से मजबूत होना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि पुलिस की वर्दी शक्ति नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का प्रतीक है. साथ ही उन्होंने वर्ष 2025 में प्रदेश को नक्सलवाद के खतरे से मुक्त करने की उपलब्धि का उल्लेख करते हुए साइबर अपराध और नशे को समाज के सामने उभरती गंभीर चुनौतियां बताया.

ईओडब्ल्यू के समक्ष पेश हुए अभिनव बरोलिया

विशेष संवाददाता

भोपाल, 9 जून. कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता अभिनव बरोलिया मंगलवार को गौमाता संरक्षण एवं कल्याण से जुड़े कथित अनियमितताओं के मामले में अपना बयान दर्ज कराने आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) पहुंचे.

उन्होंने मामले में न्याय की मांग करते हुए जांच एजेंसी को संबंधित तथ्य एवं दस्तावेज सौंपे तथा निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की. ईओडब्ल्यू अधिकारियों ने प्रस्तुत दस्तावेजों और तथ्यों का संज्ञान लेते हुए मामले की गहन जांच करने तथा जांच के निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है. बयान दर्ज कराने के बाद अभिनव बरोलिया ने कहा कि गौमाता के सम्मान और न्याय के लिए उनका संघर्ष निरंतर जारी रहेगा. उन्होंने जांच प्रक्रिया पर भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि एजेंसी मामले में लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष, पारदर्शी और तथ्यों पर आधारित जांच करेगी. बरोलिया ने कहा कि सत्य सामने लाना और दोषियों को जवाबदेह बनाना आवश्यक है.

विवाद के बाद दो मासूम बच्चियों की हत्या

कई लोगों को हिरासत में लिया गया

धार, 09 जून. जिले के राजोद थाना क्षेत्र में आपसी विवाद के बाद दो मासूम बच्चियों की कथित रूप से पानी के होद में डुबोकर हत्या कर दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

राजोद थाना क्षेत्र के ग्राम जामपाड़ा में सोमवार रात एक महिला से जुड़े विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच बैठक आयोजित की गई थी. बैठक में विवाद का समाधान नहीं निकलने पर दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया. बताया गया है कि इसके बाद कुछ लोगों ने गांव में पहुंचकर मारपीट और उपद्रव किया. इस दौरान अफरा-तफरी की स्थिति निर्मित हो गई. आरोप है कि उपद्रव के बीच दिनेश कटारा की दो पुत्रियों ऋषिका (चार वर्ष) और शिवानी (पांच वर्ष) को पानी के होद में डुबो दिया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई.

घटना के सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है

घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. सूचना मिलते ही राजोद थाना पुलिस तथा वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया. क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. सरदारपुर अनुविभागीय पुलिस अधिकारी विश्वदीप सिंह परिहार के नेतृत्व में पुलिस ने घेराबंदी कर कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है. उनसे पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है तथा घटना के सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.

नहीं बढ़ेगी तबादलों की समय-सीमा

15 तक करें तबादले

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 9 जून. महज एक पखवाड़े के लिए तबादलों की अनुमति की समय-सीमा को और बढ़ाये जाने की मंत्रियों की उम्मीदों को झटका लगा है. मंगलवार को अनौपचारिक कैबिनेट के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रियों को साफ सचेत कर दिया कि यदि आप तबादलों के समय में और बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करें.

राज्य सरकार ने स्थानांतरण के लिए 15 जून की समय-सीमा निर्धारित की है. सभी विभाग 15 जून तक स्थानांतरण नीति का पालन करते हुये स्थानांतरण की कार्यवाही पूरी कर लें. समय-सीमा नहीं बढ़ेगी.

वहीं मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस वर्ष कमजोर मानसून के पूर्वानुमान और खाड़ी में युद्ध की स्थिति के कारण उर्वरक की स्थिति पर निरंतर नजर रखी जा रही है. खाड़ी की वर्तमान स्थिति को देखते हुये उर्वरक की उपलब्धता भी प्रभावित हो रही है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उर्वरक की उपलब्धता की स्थिति के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी और एक मोबाइल नंबर स्थापित करने के निर्देश दिए. उन्होंने बताया कि ये नोडल अधिकारी प्रभारी मंत्री और सांसदों, विधायकों के साथ समन्वय करेंगे और जिले में उर्वरक की आपूर्ति तय मात्रा के हिसाब से उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निभाएंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि 9 जून का दिन विशेष महत्व का है.

उन्होंने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून तक विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है. इसके तहत 5 जून 2026 विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रत्येक विकास खण्ड, नगरीय निकायों में एक पेड मां के नाम अभियान संचालित किया गया. अभियान में प्लास्टिक अपशिष्ट की सफाई एवं शासकीय कार्यालयों, स्कूल एवं छात्रावास में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जायेगा.

सड़क दुर्घटना में युवक की मृत्यु के बाद उपद्रव

भिण्ड. मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले में सड़क दुर्घटना में एक युवक की मृत्यु के बाद आक्रोशित लोगों द्वारा कथित रूप से ट्रक चालक के साथ मारपीट और वाहन में आगजनी किए जाने के मामले में पुलिस ने 13 नामजद तथा पांच अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है. पुलिस सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश के कैलिया थाना क्षेत्र के सलैया गांव निवासी हिम्मत रजक की मोटरसाइकिल की टक्कर एक ट्रक से हो गई. दुर्घटना में हिम्मत रजक की मौके पर मृत्यु हो गई, जबकि उनके चाचा दिनेश रजक गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद मौजूद लोगों ने ट्रक चालक सोनू रायकवार को पकड़ लिया.

हाईटेक सिग्नलिंग से सशक्त हुआ रेलखंड

कल्हार-बरेठ-गंजबासौदा रेलखंड हुआ हाईटेक, शुरू हुई ऑटोमैटिक सिग्नलिंग

भोपाल, 9 जून. पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल ने रेल सुरक्षा और परिचालन क्षमता बढ़ाने की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. डीआरएम पंकज त्यागी के मार्गदर्शन में कल्हार-बरेठ-गंजबासौदा रेलखंड पर 9 जून 2026 से आधुनिक ऑटोमैटिक ब्लॉक सिग्नलिंग प्रणाली शुरू कर दी गई है.

करीब 19.57 किलोमीटर लंबे इस रेलखंड में स्थापित नई प्रणाली से ट्रेनों का संचालन अधिक सुरक्षित, तेज और कुशल होगा. पूरी व्यवस्था सीमेंस इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से संचालित होगी, जिसकी निगरानी स्टेशन मास्टर कक्ष में लगे वीडियो डिस्प्ले यूनिट के माध्यम से की जाएगी.

परियोजना के तहत कल्हार-बरेठ और बरेठ-गंजबासौदा खंड में आधुनिक रिले हट बनाए गए हैं. संचार व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 24 फाइबर ऑप्टिक केबल की रिंग संरचना और 48-कोर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्थापित किया गया है. साथ ही 45 ऑटो सिग्नल और 196 डेटा पॉइंट लगाए गए हैं.

नई तकनीक से ट्रेनों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखने, रेल यातायात क्षमता बढ़ाने और समयपालन में सुधार होगा. भविष्य में यह नेटवर्क 'कवच' जैसी उन्नत सुरक्षा प्रणाली और यात्री सूचना सेवाओं के लिए भी उपयोगी साबित होगा. रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस परियोजना से सुरक्षा, विश्वसनीयता और संचालन दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.

आयुष्मान योजना | देश भर में 44 करोड़ से अधिक लोगों ने बनवाए आयुष्मान कार्ड

आयुष्मान कार्ड बनाने में एमपी दूसरे स्थान पर

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 09 जून. देश भर में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत योजना) के तहत 44. 14 करोड़ से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं.

करीब सरकार देश के 40% वंचित परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज दे रही है. वहीं देश भर में बने स्वास्थ्य के तहत बने आयुष्मान कार्ड में मध्यप्रदेश दूसरे स्थान पर है. तो उत्तर प्रदेश 5 करोड़ 81 लाख 66 हजार 847 कार्ड धारकों के साथ पहले स्थान पर है. मध्यप्रदेश में अब तक 4 करोड़ 48 लाख 63 हजार 781 लोगों ने अयुष्मान कार्ड बनवा लिये हैं. इसके बाद बिहार 4 करोड़ 13 लाख 15 हजार 080 के साथ तीसरे, महाराष्ट्र 4 करोड़ 5 लाख 96 हजार 910 के साथ चौथे और ओडिशा 3 करोड़ 42 लाख 73 हजार 022 के साथ पांचवे स्थान पर है. देश में पुरुषों के नाम 22 करोड़ 35 लाख 88 हजार 981 और महिलाओं के नाम 21 करोड़ 78 लाख 16 हजार 370 आयुष्मान कार्ड दर्ज हैं. अन्य श्रेणी में 4 लाख 13 हजार 516 कार्ड बनाये गये. अक्टूबर 2024 में शुरू हुई आयुष्मान भारत वय वंदना योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के अब तक 1 करोड़ 20 लाख बुजुर्ग नामांकित हो चुके हैं. जिन्होंने 3,000 करोड़ के 13 लाख 84 हजार से अधिक के उपचार का लाभ लिया है.

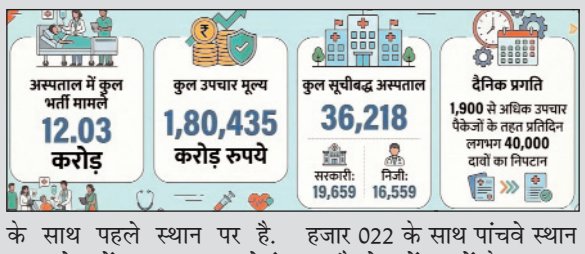

सबसे ज्यादा इलाज वाले विभाग	कुल मरीज
जनरल मेडिसिन	64,71,325
नेत्र विज्ञान	27,89,458
जनरल सर्जरी	16,40,580
प्रसूति एवं स्त्री रोग	16,00,568
मेडिकल ऑन्कोलॉजी (कैंसर)	14,16,316
सबसे ज्यादा हुई विशिष्ट प्रोसीजर	**कुल मरीज**
नियमित किडनी डायलिसिस	42,57,594
मोतियाबिंद सर्जरी	21,23,126
एनिमल बाइट (साँप काटने को छोड़कर)	11,96,882
सिजेरियन प्रसव	5,03,225
लैप्रोस्कोपिक सर्जरी (दूरबीन विधि)	4,05,205

परीक्षा केंद्रों पर सुविधाओं की मांग

विद्यार्थियों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराया जाना आवश्यक

धार, 09 जून. री-नीट परीक्षा के मद्देनजर धार जिले में परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने आज कलेक्टर राजीव रंजन मीणा को ज्ञापन सौंपा.

जिला कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह ठाकुर तथा पार्षद ईश्वर सिंह ठाकुर ने कलेक्टर से मुलाकात कर कहा कि पेपर लीक और परीक्षा संबंधी विवादों के कारण छात्र पहले से ही मानसिक दबाव में हैं. ऐसे में दोबारा आयोजित होने वाली परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों को बेहतर और तनावमुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है. ज्ञापन में परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त कूलरों की व्यवस्था, शुद्ध एवं ठंडे पेयजल की उपलब्धता, प्रत्येक परीक्षा कक्ष में बड़ी दीवार घड़ी लगाने तथा समय की सूचना के लिए सायरन अथवा घंटी की व्यवस्था करने की मांग की गई है.

कांग्रेस पार्षदों ने यह भी मांग की कि परीक्षा केंद्रों को शांत क्षेत्रों में स्थापित किया जाए और परीक्षा अवधि के दौरान संबंधित क्षेत्र को साइलेंट जोन घोषित किया जाए, ताकि बाहरी शोर-शराबे से विद्यार्थियों की एकाग्रता प्रभावित न हो.

उन्होंने कहा कि जिले के बड़ी संख्या में विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, इसलिए प्रशासन को समय रहते सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी चाहिए. कलेक्टर ने ज्ञापन प्राप्त कर आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है.